

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» घर में आणगी सुख-समृद्धि ...



विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

छग में लागू होगी "कृषक उन्नति योजना"

अब किसानों को प्रति एकड़ 19257 रुपए मिलेगी आदान सहायता राशि

रायपुर. साय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है. खरीफ 2023-24 से "कृषक उन्नति योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया.

राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्ट लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है. विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है. मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी और तदनुसार अनुपांगिक कार्यवाही करने के लिए विभाग को अधिकृत



किया जाएगा. मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फेर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

लोकतंत्र सेनानियों-आश्रितों को सम्मान राशि

प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों-आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी. एक मार्च से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रुपए प्रतिमाह, एक से 5 माह तक के निरूद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रुपए प्रतिमाह और पांच माह तथा अधिक

निरूद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा. भारत में घोषित आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा-डीआईआर के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम-2008 बनाया गया था, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 जनवरी 2020 तथा 29 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर निरस्त कर दिया गया था. मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च न्यायालय ने 26 मई 2020 को पारित आदेश के परिणाम में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए लोकतंत्र सेनानियों

(मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया. पूर्व अनुसूचित प्रतिमाह सम्मान राशि पुनः प्रारंभ की जाती है और सम्मान राशि बंद होने से लेकर पुनः प्रारंभ होने तक की अवधि की एरियर्स राशि 01 नवम्बर 2024 को प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

पृथक सुशासन विभाग

प्रदेश में राज्य सरकार को जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग के लिए और जनसम्पत्तियों के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है. इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए

पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. नये विचारों और क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे. विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा. इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे.

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए अनुदान एवं शासकीय भूमि आवंटन के लिए योजना का नामकरण अटल बिहारी योजना किया गया था. जिसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था. मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना का नामकरण पुनः "अटल बिहारी योजना" करने का निर्णय लिया गया.

अब तक 300 माननीयों को जेल

अमित शर्मा

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर की अदालत ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है। चूंकि, दो साल से अधिक अवधि की सजा पाने के बाद कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, धनंजय सिंह की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो गई है। सजा पाने के बाद धनंजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि यह उनकी राजनीति को समाप्त करने की साजिश है। जिस दिन भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और जौनपुर लोकसभा सीट पर पूर्व कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह को चुनाव में उतारा था, उसी दिन धनंजय सिंह ने यह घोषणा कर दी थी कि वे जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे। अपनी सजा पर रोकर लगाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। यदि उनकी सजा पर स्थगन मिल जाता है, तो वे चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन धनंजय सिंह पहले सांसद या जनप्रतिनिधि नहीं हैं, जिन्हें अदालत से सजा पाने के बाद अपनी राजनीति खत्म होने का डर सता रहा है। अब तक एमपी-एमएलए कोर्ट ने लगभग 300 जनप्रतिनिधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है।

इनमें से ज्यादातर नेताओं की हमेशा-हमेशा के लिए राजनीति खत्म हो गई। इन बड़े नेताओं को हुई जेल- एमपी-एमएलए कोर्ट से यूपी के कई बड़े अपराधी नेताओं को जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और बाहुबली मुख्तार अंसारी, उनके

भाई अफजाल अंसारी, बेटा अब्दुल्ला अंसारी जैसे अपराधी नेताओं को अलग-अलग मामले में सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा कुलदीप सेंगर को सजा मिलने के कारण उनकी राजनीति भी हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। शहाबुद्दीन अंसारी जैसे आपराधिक नेता कुछ राजनीतिक दलों के लिए एक असेट का काम करते थे। वे न केवल स्वयं चुनाव जीत रहे थे, बल्क अपने सामाजिक प्रभाव के कारण कई अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारों को

जिताने-हराने का काम कर रहे थे। लेकिन इनमें से कई बड़े आपराधिक नेताओं को जेल की सजा हुई और उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। शहाबुद्दीन के भी एक हत्याकांड में अपराधी ठहराए जाने के बाद उसकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। सही दिशा में काम कर रही ये कोर्ट- सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट को इसीलिए स्थापित किया गया था क्योंकि अदालत मुकदमों में बोज़ के कारण सांसदों-विधायकों पर लंबे समय तक केस चलते रहते थे। इस दौरान उनकी राजनीति भी चलती रहती थी, जबकि पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिलती थी।

ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों के मुकदमों में तेज सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए अदालतों की स्थापना की गई। अब तक लगभग 300 सांसदों-विधायकों को विभिन्न मामलों में अलग-अलग सजाएं हो चुकी हैं। यह दिखाता है कि एक सही कदम उठाने से लोगों को न्याय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता पूरी तरह लागू होने के बाद न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।

76 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले



रायपुर। राज्य शासन ने बड़ी प्रशासनिक करते हुए एक साथ 76 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है. पुलिस विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश और अधिकारियों के नाम की लिस्ट जारी की गई है. आदेश के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में एएसपी प्रभावित हुए हैं. बता दें कि कौतिल राठौर अब रायपुर ग्रामीण के एडिशनल एएसपी होंगे. वहीं एडिशनल एएसपी अभिषेक माधेश्वरी

को जगरगुंडा सुकमा कैंप में पोस्टिंग दी गई है. इसी तरह एडिशनल एएसपी नीरज चंद्रकार को बिलासपुर का एएसपी, जेपी बहई को एएसपी अंतागढ़ कांकेर, एएसपी पीतांबर पटेल को मोहला मानपुर, एएसपी सुखनंदन राठौर को एएसपी दुर्गा शहर और आकाश राव गिरिपुंजे को सुकमा एएसपी का प्रभार दिया गया है.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अधिकारियों का हुआ तबादला- छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ कई अधिकारियों का तबादला हुआ है. राज्य शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज देर शाम इसका आदेश जारी किया गया है. आदेश के साथ जारी अधिकारियों के नामों की लिस्ट में 13 अधिकारियों का नाम शामिल है जिन्हें नवीन पदस्थापना दी गई है

25 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार नई दिल्ली।

बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े एक आरोपी के खिलाफ जारी इंटरपोल रेड नोटिस होने के बाद उस अमेरिका में पकड़ा गया, जिसे भारत वापस लाया गया। अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 25 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में आरोपी राजीव मेहता ने बैंक ड्रॉप्ट कर रोक लिया था, जिसके बाद आरोपी ने पैसा निकाल लिया था। गौरतलब है कि वर्ष 2000 से आरोपी मामले में फरार चल रहा था।

चुनाव आयोग ने राहुल को दी हिदायत मोदी पर सोच-समझकर बयान दें

नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को राहुल गांधी को एक सलाह जारी की और कांग्रेस नेता को प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करते समय सावधान और सतर्क रहने को कहा। एएनआई ने बुधवार को बताया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और उनके जवाब सहित

प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियों से संबंधित मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, भारत के चुनाव आयोग ने उन्हें भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके पत्नी और जेबकतरे तंज के मद्देनजर अपने सार्वजनिक भाषणों में अधिक सावधान और सतर्क रहने को कहा है। चुनाव आयोग पिछले साल दिसंबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर काम कर रहा था। अदालत ने चुनाव आयोग से 22 नवंबर के उस भाषण के लिए राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेबकतरा कहा था। अदालत ने

कहा कि बयान अच्छे स्वाद में नहीं था और ईसीआई से आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार कार्य करने को कहा। पोल पैनल ने राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए भी कहा। 1 मार्च की अपनी सलाह में, चुनाव आयोग ने चेतावनी दी कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एडवाइजरी में यह भी चेतावनी दी गई है कि जिन पार्टी प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, उन्हें आदर्श आचार संहिता का बार-

अमेठी से नाम घोषित करने में इतना समय क्यों : स्मृति ईरानी

नई दिल्ली। अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि उन्हें नहीं पता कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस इस सीट से किसे मैदान में उतारेगी लेकिन देरी ही पार्टी के लिए हार का संकेत है। स्मृति ईरानी का बयान उन तीव्र अटकलों के बीच आया है कि कांग्रेस 2019 की हार के बाद एक बार फिर इस सीट के लिए राहुल गांधी को दोहराएगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह अजीब है क्योंकि पहली बार पार्टी को अमेठी से उम्मीदवार का नाम घोषित करने में इतना समय लग रहा है। अमेठी उम्मीदवार की घोषणा करने से पहले इतना मंथन किया जा रहा है। यह अपने आप में हार का संकेत है। बता दें कि अमेठी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि पार्टी नेता राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद लौटे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बुधवार को बताया कि राहुल गांधी ही अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे जिसकी घोषणा शीघ्र हो जायेगी। सिंघल ने बताया कि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गयी है, कार्यकर्ता अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं।

लोकसभा का चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखने पर विचार कर रहे हैं। हरियाणा राज्य में स्थित रोहतक निर्वाचन क्षेत्र को कथित तौर पर उनकी संभावित चुनावी लड़ाई का मैदान माना जा रहा है। हरियाणा से अपने मजबूत संबंधों के लिए जाने जाने वाले, हड्डा की उम्मीदवारी राज्य में उनकी लोकप्रियता और स्थानीय प्रभाव का लाभ उठाने के लिए भाजपा द्वारा एक रणनीतिक कदम प्रतिनिधित्व कर सकती है। विभिन्न बॉलीवुड हिट फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसित अभिनेता ने अभी तक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। हरियाणा के मध्य में स्थित रोहतक, भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युद्धक्षेत्र प्रस्तुत करता है।

लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अभिनेता रणदीप हुडा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी लोकसभा चुनाव में अभिनेता रणदीप हुडा को रोहतक सीट से संभावित उम्मीदवारी के संकेत दिए हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि अभिनेता रणदीप हुडा लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखने पर विचार कर रहे हैं। हरियाणा राज्य में स्थित रोहतक निर्वाचन क्षेत्र को कथित तौर पर उनकी संभावित चुनावी लड़ाई का मैदान माना जा रहा है। हरियाणा से अपने मजबूत संबंधों के लिए जाने जाने वाले, हड्डा की उम्मीदवारी राज्य में उनकी लोकप्रियता और स्थानीय प्रभाव का लाभ उठाने के लिए भाजपा द्वारा एक रणनीतिक कदम प्रतिनिधित्व कर सकती है। विभिन्न बॉलीवुड हिट फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसित अभिनेता ने अभी तक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। हरियाणा के मध्य में स्थित रोहतक, भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युद्धक्षेत्र प्रस्तुत करता है।

शाहजहां शेख को सीबीआई ने हिरासत में लिया संदेशखाली के आरोपी शेख शाहजहां को बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया। यह सुपुर्गी तब हुई जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्बाध तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता को हिरासत में नहीं सौंपने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना ??के लिए खिंचाई की जानी चाहिए, जिस पर संदेशखाली में कई महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सीबीआई ने दावा किया कि बंगाल सीआईडी ??ने शेख शाहजहां को जांच एजेंसी को सौंपने के उच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश का पालन नहीं किया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि सरकार ने शाहजहां को हिरासत में नहीं दिया।

शाहजहां शेख को सीबीआई ने हिरासत में लिया

संदेशखाली के आरोपी शेख शाहजहां को बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया। यह सुपुर्गी तब हुई जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्बाध तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता को हिरासत में नहीं सौंपने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना ??के लिए खिंचाई की जानी चाहिए, जिस पर संदेशखाली में कई महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सीबीआई ने दावा किया कि बंगाल सीआईडी ??ने शेख शाहजहां को जांच एजेंसी को सौंपने के उच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश का पालन नहीं किया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि सरकार ने शाहजहां को हिरासत में नहीं दिया।

गुजरात कांग्रेस में नहीं थम रहा इस्तीफे का सिलसिला

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर विधायक अर्जुन मोहवाडिया के इस्तीफे के ठीक दो दिन बाद आज एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया। माणवदर सीट से विधायक अरविंद लदानि ने आज यहां राज्य विधानसभा अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी को उनके आवास पर अपना इस्तीफा सौंप दिया। लदानि ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस नेता का ताजा इस्तीफा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की %भारत जोड़े न्याय यात्रा% के गुजरात आगमन से एक दिन पहले हुआ है। इससे पहले राजुला में लदानि ने गुजरात बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल के साथ बैठक की। लदानि ने पिछले तीन दिनों से मीडियाकर्मियों या कांग्रेस नेताओं के कॉल का जवाब नहीं दिया है।

राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन से देश पर भी असर-अदालत

नई दिल्ली। केरल सरकार से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों द्वारा राजकोषीय कुप्रबंधन एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर केंद्र को चिन्तित होना चाहिए क्योंकि ऐसे मुद्दे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को मतभेदों को दूर करने की सलाह दी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी तब सामने आई जब अदालत केरल सरकार द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा था। जिसमें भारत सरकार पर उधार लेने की सीमा लगाकर राज्य के वित्त को विनियमित करने के लिए राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने मुद्दे को सुलझाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य नहीं रुकनी चाहिए। सुनवाई के दौरान खंडपीट ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेने में सक्षम हैं। मामले के समाधान के लिए एक साथ बैठें और इसे हल करें। केरल सरकार ने 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 15 फरवरी को हुई बैठक विवादास्पद मुद्दे को सुलझाने में असफल रही।

नवीन पटनायक ने बुलाई बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री के दौरे से मिले थे संकेत लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा बीजेडी का हो सकता है गठबंधन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकसभा चुनाव के लिए ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (बीजेडी) के साथ गठबंधन कर सकती है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। खबर यह भी है कि बीजेपी के साथ सीट बंटवारे और गठबंधन की अटकलों के बीच बीजू जनता दल (बीजेडी) के वरिष्ठ नेता ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के धुवनेश्वर स्थित आवास पर पहुंचे। ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनावों में, बीजेडी ने 12 सीटें जीतीं, भगवा पार्टी को 8 सीटें मिलीं जबकि एक सीट कांग्रेस को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो

मंगलवार को ओडिशा में थे, ने कहा कि भाजपा सरकार ओडिशा को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का प्रवेश द्वार बनाने की कोशिश कर रही है। जाजपुर जिले के चंडीखोले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ओडिशा में भारी निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओडिशा दौरे के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की नवीन पटनायक की सरकार पर किसी तरह की बात कहने से बचते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस व्यवहार के साथ

ही भाजपा और बीजेडी के बीच गठबंधन की अटकलें भी तेज हो गई थीं। हालांकि बीजेपी और बीजेडी दोनों ही पार्टियों ने अब तक गठबंधन को लेकर किसी तरह की टिप्पणी खुलकर नहीं की है। दोनों दलों के नेता लगातार गठबंधन की संभावना से बचते दिख रहे हैं। नवीन पटनायक और भाजपा चाहे यूपीए हो या एनडीए, भारत सरकार के साथ स्थिर संबंधों से नवीन पटनायक को फायदा होता है। ओडिशा की अधिकांश लोकसभा सीटें जीतने का उनका रिकॉर्ड मोदी की लोकप्रियता से भी नहीं टूटा। हालांकि, मोदी और

पटनायक के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन ओडिशा में बीजेपी ने बीजेडी के जोरों में संघ लगा ली है। दोनों पार्टियों हमेशा एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी नहीं थीं। 1997 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नवीन पटनायक ने पहली बार चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और उपचुनाव जीता। जब एक साल बाद जनता दल विभाजित हो गया, तो पटनायक ने अपनी पार्टी बनाई और केंद्र में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री बने। इससे नई

क्षेत्रीय पार्टी बीजेडी की राजनीतिक शुरुआत हुई, जो आज तक ओडिशा में 2000 और 2004 में दो विधानसभा चुनाव भी लड़े। 2008 में दोनों दलों के बीच गठबंधन टूट गई। दोनों दलों के बीच अनौपचारिक सौहार्द हमेशा एक-दूसरे के लिए आपसी सम्बंधन पर आधारित रहा है। मोदी सरकार ने अतिरिक्त उधार अनुमति के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देकर ओडिशा की मदद की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य को वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 2,725 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की अनुमति मिली है।

महाराष्ट्र में महायुति की बैठक महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर गुरुवार को महायुति की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई. बैठक में यह विश्वास व्यक्त किया गया कि महायुति लोकसभा चुनाव एकजुटता और मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। सीट आवंटन को लेकर महायुति की एक और बैठक होगी। इसके बाद तीनों पार्टियों के सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। राज्य में 48 लोकसभा सीटें हैं और जानकारी सामने आ रही है कि तीनों पार्टियों के सीट बंटवारे का प्रारंभिक मसौदा तैयार हो चुका है। राज्य में तीनों दलों के नेता स्थानीय स्तर पर चर्चा करेंगे और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों और उम्मीदवारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे।



राजस्व के पेंडिंग मामले में हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बिलासपुर निवासी महिला ने तहसीलदार पर राजस्व संबंधित मामले निराकृत नहीं करने और मामले को लंबे समय तक अटकाने के आरोप लगाए। साथ ही हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और राजस्व सचिव को शपथ पत्र में प्रदेश के लंबित राजस्व मामलों की जानकारी देने को कहा है।



रही लेकिन जब मामला निराकृत नहीं हुआ तो महिला ने कोर्ट की शरण ली। जमीन निराकरण के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कलेक्टर से निराकरण समेत कई जानकारियां शपथ पत्र में मांगी थी। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीपी में शासन की ओर से जवाब दिया गया जिसमें बिलासपुर में 497 अविवादित और 197 विवादित मामले नामांतरण के लंबित हैं। जानकारी के बाद कोर्ट ने कहा कि काम ऑनलाइन होने और 90 दिन में निराकृत करने का आदेश होने के बाद भी

मामले लंबित होना आश्चर्य है। यदि ये आंकड़ा सिर्फ बिलासपुर का है तो प्रदेश भर की क्या स्थिति होगी। इस मामले में कोर्ट ने मुख्यसचिव और राजस्व सचिव को शपथ पत्र के साथ मामले की जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने पहले की सुनवाई में कलेक्टर बिलासपुर से तहसील कार्यालय में लंबित मामलों की जानकारी मांगी थी और इसे ठीक करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एक ही जगह पर जमे राजस्व निरीक्षक, पटवारी का तबादला करने के साथ ही कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया था।

सभी थानों में सीसीटीवी लगाएं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डीजीपी को निर्देश

बिलासपुर। पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग की। रायगढ़ के कोतारा रोड पुलिस पर आरोप लगा है। याचिकाकर्ता शशि भूषण ने पत्नी के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने बताया कि झूठे केस से नाम हटाने के लिए कोतारा रोड पुलिस ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की थी। पैसा नहीं देने पर उन्हें पुलिस पकड़ कर थाना ले आई और उनके पति के कपड़े उतार कर लॉकअप में उनकी पिटाई की। याचिकाकर्ता ने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष में पढ़ने के दौरान शशि भूषण ने एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर 50-50 हजार रुपये लेकर लोगों से ठगी की थी। पुलिस के केस दर्ज करने के बाद शशि भूषण ने निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई। जहां से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद पत्नी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जानकारी देते हुए जमानत की मांग की। इस मामले में जस्टिस एन के व्यास की बेंच में सुनवाई हुई। बहस के दौरान बताया गया कि उन पर झूठा आरोप लगा है। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। जमानत देने के साथ ही हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने डीजीपी को सभी थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इसकी मॉनिटरिंग जिले के एसपी से करवाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इसका नियमित ऑपरेंट भी किया जाना आवश्यक है।



भाजपा ने नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया

जगदलपुर। नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। प्रशासन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 11 मार्च की तारीख तय की गई थी। इसके साथ ही नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक भी इसी दिन रख दी गई। अब सामान्य सभा की तारीख निगम के द्वारा बदली जा रही है। जिसका विरोध के भाजपा पार्षदों द्वारा किया जा रहा है। भाजपा के पार्षदों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन कर तारीख बदलने का विरोध किया।



नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने आरोप लगाया है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी महापौर के खिलाफ भी पूर्व में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। अविश्वास प्रस्ताव के दिन कांग्रेस के पार्षद बहुमत साबित करने पहुंचे ही नहीं। आगे उन्होंने कहा, इसी तरह का पत्र एक बार फिर कांग्रेस पार्टी आजमाना चाह रही है। महापौर और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही शहर में विकास के कार्य थम गए हैं। महापौर और अध्यक्ष के द्वारा सामान्य सभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा रही है।

राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक को सालों बाद भी नहीं मिला लाभ

डीईओ से मिले टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि

कबीरधाम। कबीरधाम में छग टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमेंडल ने जिलाध्यक्ष रमेश कुमार चन्द्रवंशी के नेतृत्व में जिला शिक्षक अधिकारी महेन्द्र गुप्ता से मुलाकात कर शिक्षक संघ की स्थानीय समस्याओं अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका संधारण, जीपीएफ कटौती का पासबुक संधारण, जीआईएस कटौती, पदोन्नत प्रधान पाठकों के वेतन का अंतर राशि, शिक्षकों के नियमविरुद्ध काटे गए वेतन की वापसी, राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक को अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा किया। चर्चा के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि पंडरिया ब्लॉक के ग्राम सिंगपुर स्कूल में संधारण शिक्षक राजर्षि पाण्डेय को वर्ष 2016 में राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया था।



इस सम्मान को प्राप्त करने वाले शिक्षक को अतिरिक्त वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने का नियम है, लेकिन आज सात साल में इसका लाभ नहीं दिया जा सका है। इसके अलावा सहायक शिक्षकों के उच्च शिक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अब तक जारी नहीं हुआ है, सभी डीडीओ द्वारा कैम्प लगाकर सेवा पुस्तिका का अद्यतन स्थिति में संधारण किया जाने, शिक्षक एलबी संघर्ष के जीपीएफ कटौती का पासबुक संधारित करने हेतु सभी डीडीओ को आवश्यक निर्देश दिया जाने, शिक्षक एलबी संघर्ष का पदनाम व्याख्याता, शिक्षक व सहायक शिक्षक निर्धारित है, उसके बाद भी पदनाम के साथ एलबी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद में आता है, इसके बाद भी प्रतिमाह जीआईएस कटौती 360 रुपए के बजाय केवल 300 रुपये किया जा रहा है। कवर्धा ब्लॉक में एलबी संघर्ष के शिक्षक से पदोन्नत हुए प्रधान पाठकों के माह फरवरी व मार्च 2022 के वेतन के अंतर राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। पंडरिया ब्लॉक के शिक्षक रमेश ध्रुव एवं कवर्धा ब्लॉक के सहायक शिक्षिका रश्मि देवी के एक दिन का काटे गए वेतन वापस नहीं किया गया है। डीईओ ने उक्त समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही उचित कार्रवाई का भरसा दिया है।

चिरमिरी में पत्थर की बारिश! दहशत में ग्रामीण, लगाए गंभीर आरोप

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। चिरमिरी में कोयला खदान के पास रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ओपनकास्ट कोल माइन के 100-200 मीटर के दायरे में रहवासी इलाका है। इसके बावजूद बिना गाइडलाइन फॉलो किए हेवी ब्लास्टिंग की गई। ग्रामीणों ने एसईसीएल कर्मचारियों पर तय गाइडलाइन फॉलो किए बगैर हेवी ब्लास्टिंग करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय निवासी उपेंद्र सिंह ने बताया, जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े ब्लास्टिंग के बाद घर की छत पर गिरे हैं। कुछ पत्थर के टुकड़े मंदिर में भी गिरे हैं। अच्छी बात यह है कि लोग बाल बाल बच गए हैं।



स्थानीय निवासी उपेंद्र सिंह ने कहा गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। कॉलोनी के 100 से 200 मीटर दूरी पर ब्लास्टिंग के लिए प्रॉपर गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। यह एसईसीएल की लापरवाही है। आज कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय निवासी उपेंद्र सिंह ने बताया, जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े ब्लास्टिंग के बाद घर की छत पर गिरे हैं। दूसरी जगह भी बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। मंदिर को भी पार कर बोल्टर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों की शिकायत पर चिरमिरी तहसीलदार शशिकांत मिश्रा और एसडीएम वीएस मरकम मोंके पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के घरों और मंदिर का निरीक्षण किया। एसईसीएल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस घटना को लेकर एसडीएम ने कहा है कि पूरी तरह से जांच होगी। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। तहसीलदार शशिकांत मिश्रा ने कहा स्थानीय लोगों से घटना की सूचना मिलते ही मैं और एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे। हमने आस पास निरीक्षण किया तो वहां बोल्टर पड़े हुए हैं, चिंताजनक स्थिति है। लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा ना हो। ग्रामीणों की मानें तो यह पहला मौका नहीं है, जब घरों में पत्थर गिरे हैं। कोयला उत्खनन के लिए हेवी ब्लास्टिंग से कई बार ऐसा वाक्या सामने आया है। घरों की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। ग्रामीणों को जान माल का खतरा बना रहता है।

विधायक की बेटी मोनिका सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी विश्व हिंदू महासंघ छत्तीसगढ़ मातृ शक्ति विंग की बनी प्रदेश उपाध्यक्ष

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह की सुपुत्री को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अधिवक्ता मोनिका सिंह को विश्व हिंदू महासंघ छत्तीसगढ़ मातृ शक्ति विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। मोनिका सिंह की नियुक्ति विश्व हिंदू महासंघ मातृ शक्ति विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष करिश्मा सिंह हाड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष पुष्पराज सिंह बघेल की अनुशंसा पर की है। धार्मिक कार्यों में बड़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली मोनिका समातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर लंबे समय से सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपनी नियुक्ति को लेकर महासंघ के प्रति आभार जताते हुए अधिवक्ता मोनिका सिंह ने कहा कि जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझे दायित्व मिला है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। मोनिका सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं विश्व हिंदू महासंघ समय-समय पर हिंदुत्व को लेकर लोगों को



जागरूक करता है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मां कालका पीठाधीश्वर कालका जी मंदिर दिल्ली के महंत सुरेन्द्रनाथ अवधूत हैं। यह संघ कई वर्षों से हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। विश्व हिंदू महासंघ मातृ शक्ति विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई अधिवक्ता मोनिका सिंह ने लॉ से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। मोनिका सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहती हैं। मोनिका सिंह पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और भरतपुर सोनहत विधानसभा से विधायक रेणुका सिंह की बेटी हैं।

गन्ना किसानों का 46 करोड़ रुपये अटका, 11 को चक्काजाम



कबीरधाम। कबीरधाम के किसान आने वाले 11 मार्च को समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के बैनर तले चक्काजाम की तैयारी में हैं। दरअसल, जिले के गन्ना किसानों का गन्ना बेचने के एक माह बाद राशि नहीं मिली है। यह प्रदर्शन 11 मार्च दिन सोमवार दोपहर एक बजे से एनएच-30 बिलासपुर रोड परसवारा चौक पंडरिया में किया जाएगा। किसानों ने पंडरिया एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के जिला अध्यक्ष सोनी वर्मा ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक़र कारखाना पंडरिया में किसानों का 46 करोड़ रुपये व भोरमदेव सहकारी शक़र कारखाना ग्राम राम्हेपुर में 12 करोड़ रुपए अटका पड़ा है। रुपये नहीं मिलने पर किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है।

लकड़बग्घे के हमले में चार ग्रामीण हुए घायल

कोंडगांव। जिले के माकड़ी ब्लॉक में लकड़बग्घा आए दिन लोगों पर हमला कर रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। लकड़बग्घा ने बुधवार को एक बार फिर ग्रामीणों पर हमला कर दिया। लकड़बग्घे के हमले में चार ग्रामीण घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। माकड़ी के डॉ सतीश नायक ने बताया, मरीजों को सिर और हाथों में लकड़बग्घा के काटने के निशान हैं, मरीज को प्राथमिक उपचार दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माकड़ी ब्लॉक के ग्राम तितरवंड की लीलाबाई मंडावी और पति हीरामन मंडावी दोनों रात में बरामदे में सोए हुए थे। देर रात करीब 1 बजे लकड़बग्घे ने लीलाबाई पर हमला कर दिया। पत्नी को बचाते हुए हीरामन लकड़बग्घा के सामने आ गया। लकड़बग्घे ने हीरामन को भी घायल कर दिया। इसी तरह शाम 4 उल्लेरा के राम प्रसाद मरकम अपने घर में शाम 4 बजे गाय के चारा के लिए घास काट रहे थे। तभी अचानक लकड़बग्घा ने उन पर हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया।

चित्रकोट महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम से गुलजार हुआ

जगदलपुर। चित्रकोट महोत्सव पर गंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर साहित्य और कला समाज द्वारा काव्य गोष्ठी प्रस्तुत किया गया, जिसमें सनत जैन ने हास्य काव्य, श्रीमती ममता मधु ने नारी शक्ति पर काव्य, नरेंद्र पाट्टी ने भतरी में हास्य काव्य, गीदम के विशाल आवाज द्वारा बस्तर की प्रकृति और संस्कृति व सभ्यता तथा अमित पूरब द्वारा हास्य काव्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक विनायक गोयल, कलेक्टर विजय दयाराम, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे सहित बड़ी संख्या जनप्रतिनिधिगण, श्रोता व दर्शक उपस्थित थे। इसके साथ ही अयान समूह द्वारा पियानो वादन, बास्तानार द्वारा गौर सिंग नृत्य, लामकेर के नर्तकों द्वारा गेड़ी नृत्य, दरभा के कलाकारों द्वारा परब नृत्य, कस्तुरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किलेपाल, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय मोरठपाल, डिमरापाल आश्रम की बालिकाओं द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए।

फ़्री में कार जीतने का ऑफर देकर फ़ॉर्ड, महिला लाखों गंवाए

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठगी के मामले बढ़ने लगे हैं। बिलासपुर में ठगी की दो घटनाएं हुई हैं। पहले मामले में ऑनलाइन शॉपिंग साइट में महिला को कार जीतने का झंसा दिया गया। महिला से ठग ने 11 लाख की ठगी की थी। वहीं दूसरे मामले में भी सस्ते में मकान दिलाने का झंसा दिया गया। आरोपी ने इस मामले में भी 11 लाख की ठगी की थी। सकरी थाना में ठगी का पहला मामला दर्ज हुआ। देवरीकला गांव की रहने वाली प्रियंका वस्त्रकर ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। ऑनलाइन शॉपिंग में भुगतान के लिए प्रियंका पति के अकाउंट का इस्तेमाल करती थी। इसी बीच दिसंबर 2022 में उनके घर के पते पर एक लिफाफा आया। लिफाफे में स्कैच कार्ड और अकाउंट डिटेल फॉर्म था। लिफाफे में दिए फोन नंबर पर जब महिला ने बात की। सामने वाले शख्स ने प्रियंका को बताया कि उसने कार जीती है। लेकिन इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। रजिस्ट्रेशन फीस के चक्र में प्रियंका ने अलग-अलग बैंक खातों में 11 लाख 22000 का ट्रांसफर कर दिया।

बाहर खड़े वाहनों को शरारती तत्वों ने किया आग के हवाले

कोरबा। कोरबा कोतवाली थानांतर्गत पुरानी बस्ती में एक जायलो और पिकअप वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। आग किसने और क्यों लगाई है इस बात का पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुरानी बस्ती के रहने वाले मेहराब खान रोज की तरह अपने काम से वापस लौटने के बाद घर के बाहर टाटा जाइलो वाहन को पिकअप वाहन के बगल में खड़ा कर घर के अंदर चला गया। रात लगभग 3 बजे अचानक ब्लास्ट की आवाज आई, जिसके बाद उसने तुरंत घर के बाहर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। दो वाहनों में आग लगी थी, दोनों वाहन धू धू कर जल रहे थे। वाहन मालिक ने तत्काल आसपास लोगों को बुलाया। जिसके बाद बस्ती के लोग एकत्रित हो गए। जिसके बात उन्होंने किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह आग पर काबू ना पा सके। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी।

नाराज कांग्रेस विधायक सुरक्षा व्यवस्था छोड़कर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर निकले

विधायक जनक ध्रुव बोले- जवानों को ठहराने की व्यवस्था नहीं, प्रशासन ने बताया वे प्रावधान



गरियाबंद। गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रशासन से नाराज बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव आज बुधवार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नहनबीरी मैनपुर निवास में छोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क के लिए निकल गए। इसकी जानकारी लगते ही प्रशासन स्तर में हड़कंप मच गया। बता दें कि बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके काफी घोर नक्सली क्षेत्र हैं और काफी संवेदनशील क्षेत्रों में माना जाता है। बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के

किस मरेका देवभोग में आवास की व्यवस्था नहीं है, मेरे स्वयं के रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मैं अपने सुरक्षाकर्मियों को कहां रखूंगा। इस मामले से कई बार प्रशासन को अवगत करा चुका हूं। विधायक जनक ध्रुव ने कहा मैं विपक्ष का विधायक हूं शायद इसीलिए सरकार मेरी सुरक्षा और रहने के लिए निवास की व्यवस्था नहीं कर रही है। बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। देवभोग क्षेत्र के लोगों को मुझसे मुलाकात करने के लिए 100 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। सरकार और प्रशासन मुझे व्यवस्थापिका का हिस्सा ही नहीं मानती इसलिए सुविधा नहीं दे रही है। इस मामले पर मैनपुर एसडीओपी बाजीलाल सिंह ने बताया कि विधायक जनक ध्रुव को पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त

सुरक्षा प्रदान किया गया है। लेकिन आवास उपलब्ध कराना जिला प्रशासन का काम है। आज उनके सुरक्षाकर्मियों थाना में पहुंचकर जानकारी दिए हैं कि विधायक जनक ध्रुव बैंगर सुरक्षा के दौरे पर निकल गए हैं। एसडीओपी बाजीलाल सिंह ने कहा कि विधायक सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है और इसकी सूचना देवभोग थाना में दे दी गई है। प्रशासन ने दिया नियमों का हवाला प्रशासन की ओर से एडिशनल कलेक्टर अरविंद पांडेय ने कहा कि आवास आवंटन नियम के मुताबिक एक ही जगह आवास देने का प्रावधान है। अगर उन्हें राजधानी में आवास में दिया गया है तो जिले या ब्लॉक में नहीं दिया जा सकता। जिले में लेना हो तो उन्हें राजधानी के आवास को छोड़ना होगा।

सुकमा में पल्स पोलियो की जगह आइस पैक पिलाया

सीएमओ ने कहा- शरारती तत्वों का हाथ होने की आशंका

सुकमा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पल्स पोलियो की जगह आइस पैक पिलाने के मामले में कार्रवाई हुई है। मामले में सुपरवाइजर को हटा दिया गया है। सीएमओ ने शरारती तत्वों का हाथ होने की आशंका जताई है। 3 मार्च को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत सुकमा के कोंटा विकासखंड के एलमागुंडा में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। इस दौरान एक बड़ी लापरवाही देखने मिली। ने बच्चों को पल्स पोलियो की जगह आइसपैक पिला दिया गया। जिसकी खबर तेजी से फैल गई। घटना के बाद 4 मार्च को दोबारा बीएमओ कोंटा के साथ मेडिकल टीम को एलमागुंडा भेजा गया। बच्चों का मेडिकल टेस्ट कर निगरानी में रखा गया। साथ ही हट्टे हुए बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गईं। बच्चों के मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित सभी स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ



कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के सुपरवाइजर को हटा दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश सांडिया ने कहा एलमागुंडा में पल्स पोलियो का अभियान चलाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितामिन और ट्रेनिंग लिए हुए लोग पल्स पोलियो पिलाते हैं। दोपहर 1 बजे तक लगभग 40 बच्चों को दवा पिलाई गई। दवाई पिलाने के बाद शरारती तत्वों द्वारा बोलकर पानी पिलाना बोलकर फोटो लिया गया है। पल्स पोलियो अभियान चलाकर देश को पोलियोमुक्त बनाया जा रहा है तो कुछ लोग लापरवाही कर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।

कोयलीबेड़ा नक्सल मुठभेड़

हाईकोर्ट के जज से न्यायिक जांच के लिये कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में हुये तथाकथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ की हाईकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि कांकेर जिले की पुलिस द्वारा 25 फरवरी को कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में हुये तथाकथित पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के संबंध में मुठभेड़ में मारे गये लोगों के बारे में उनके परिजनों तथा ग्रामीणों द्वारा गंभीर सवाल खड़ा किया जाना तथा कहना कि मारे गये तीनों लोग नक्सली नहीं थे उनके यह आरोप बेहद ही चौकाने वाले है तथा उन सभी के परिजनों ने मृतकों के बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मंरेगा कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सभी कुछ दिखाया है। मारे गये लोगों मृतक अनिल हिडको, रामेश्वर नेगी, सुरेश तेता की पत्नियों, माता-पिता, परिजनों एवं ग्रामवासियों का कहना है कि वे सब चावल, दाल लेकर रस्सी लेने जा रहा हूँ बोलकर निकले थे। अभी तेंदूपता बूटा कटाई का समय है। अप्रैल में तेंदूपता तोड़ाई होता है उसके



लिए सब लोग अभी रस्सी जुगाड़ कर लेते हैं। उसी को लेने ये लोग जंगल गए थे, हमारे पति नक्सली नहीं हैं, और ये लोग जो समान दिखा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। हमारे पति को नक्सली बता कर मारा गया है। ग्रामीणों की शिकायतें बेहद ही गंभीर और संवेदनशील है। आरोप पुलिस पर लगे हैं। आरोपों को गंभीरता को देखते हुये यह आवश्यक है कि इस मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की जानी चाहिये। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में इस मुठभेड़ की जांच कराई जाये।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

दीपक बैज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमितेप शुक्ल, पूर्व सांसद छाया वर्मा, एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेड़, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरुमुख सिंह होरा, महामंत्री सुबोध हरितवाल, दीपक मिश्रा, खादी ग्रामोद्योग पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी, वार रूम चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, महामंत्री अमरजीत चावला, रायपुर जिला शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा, महापौर एजाज देबर, पूर्व प्रत्याशी रायपुर ग्रामीण पंकज शर्मा, पूर्व विधायक अनिता शर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, राधेश्याम विभार उपस्थित थे।

सरकारी राशन दुकानों में करोड़ों की हेराफेरी, भरपाई के लिए खाद्य विभाग ने संचालकों को थमाया नोटिस

जिम्मेदार अधिकारियों पर नहीं हो रही कार्रवाई

कवर्धा। राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को बांटे जाने वाले खाद्य सामग्री चावल, शक्कर व चना में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले को भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने विधानसभा सत्र में जोर-शोर से उठाया था। इसके बाद से खाद्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दुकान संचालकों से अब वसूली करने में विभाग के पसीने छूट रहे हैं। वहीं सवाल यह भी उठ रहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

कबीरधाम जिले में भी शासकीय राशन दुकान संचालकों द्वारा बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सामग्री की हेराफेरी की गई है, जिसकी राशि 13 करोड़ रुपए से अधिक है। मामले की खुलासा तब हुआ जब दिसम्बर 2022 से मई 2023 तक जिले के राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 498 दुकानों में तीन हजार सात सौ इक्कीस मीट्रिक टन राशन



सामग्री चावल, शक्कर व चना कम पाया गया। इसकी कीमत लगभग 13 करोड़ 26 लाख रुपए है। इसकी भरपाई के लिए खाद्य विभाग ने सभी दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया है। वहीं हेराफेरी के मामले में तीन दुकान संचालकों पर एफआईआर व 8 दुकान को निलंबित किया गया है। शेष दुकानदारों को नोटिस थमाया गया है, लेकिन खाद्यान्न सामग्री के हेराफेरी के इस खेल में एक

भी जिम्मेदार खाद्य अधिकारी के ऊपर ठोस कार्यवाही शासन ने नहीं की है, जो बड़ा सवाल है। जिले के खाद्य अधिकारी आकांक्षा नायक ने बताया 342 दुकान संचालकों से दो हजार नौ सौ छब्बीस मीट्रिक टन खाद्य सामग्री की वसूली की जा चुकी है। पांच सौ चालीस मीट्रिक टन खाद्य सामग्री 38 दुकानदारों से तहसीलदार के माध्यम से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

बगीचा से 251

श्रद्धालुओं का जत्था हुआ अयोध्या रवाना

जशपुर। श्रीराम लला दर्शन योजना के तहत आज अयोध्या के लिए जिले के बगीचा से 251 श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था रवाना हुआ। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने पत्थलगॉव, बगीचा, पंडरापाट, सना, कुनकुरी के बुजुर्ग यात्रियों पर फुल बरसाकर उनको अयोध्या भेजा।

बैंड बाजे की धून पर नाच-गाने के साथ सभी श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना कर रहे थे। बगीचा से अम्बिकापुर पहुंचने के बाद सभी श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे।

बगीचा के दिनेश शर्मा का कहना था कि वर्षों से पंडाल में स्थापित श्रीराम लला के अब भव्य मंदिर में दर्शन करने की यात्रा निश्चित ही रोमांचित है। यहां से रामलला के दर्शन करने जा रहे लोगों के परिजन भी इसे वर्षों का एक सुनहरा सपना पूरा हो जाने की बात कर रहे हैं। बगीचा में इन श्रद्धालुओं पर फुल बरसा कर और तिलक लगाकर पूजा अर्चना के बाद उन्हें रवाना किया गया।

संक्षिप्त समाचार

रायपुर में होगा राष्ट्रीय किसान

महारसम्मेलन, मिलेगी धान की अंतर राशि

रायपुर। लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी के साईंस कॉलेज मैदान में 9 मार्च को राष्ट्रीय किसान महासम्मेलन होगा, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। किसान महासम्मेलन में मोदी की गारंटी के तहत किसानों को धान की अंतर राशि दी जाएगी। इस सम्मेलन में देशभर से किसान होंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने आज कृषि मंत्री राम विचार नेताम व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप साईंस कॉलेज मैदान पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में मजदूर व कारीगर विशेष साज सजावट कर रहे। नेताओं ने कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया।

महतारी वंदन योजना राशि वितरण

का कार्यक्रम स्थगित

रायपुर। राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में 7 मार्च को आयोजित महतारी वंदन योजना राशि वितरण का कार्यक्रम प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी का समय नहीं मिल पाने के कारण स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम में प्रधामंत्री योजना के तहत महिलाओं को पहली किश्त जारी करने वाले थे। कार्यक्रम की जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं 1000 प्रतिमाह की राशि दी जानी है।

बच्चों के जीवन और भविष्य का सुरक्षा

कवच है टीकाकरण

रायपुर। शिशुओं के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है। टीकाकरण नवजात शिशुओं के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है साथ ही बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। उप संचालक एवं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. आर. भगत ने बताया कि टीकाकरण बच्चे के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है और उन्हें विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत राज्य में 11 प्रकार के वैक्सीन लगाये जा रहे हैं जिनसे 12 प्रकार के वैक्सीन एवं जानलेवा बीमारियों से बचाव होती है। जम्म से लेकर 05 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 एवं 16 वर्ष के किशोर-किशोरियों को लगाए जाने वाले ये सभी टीके सभी शासकीय अस्पतालों एवं टीकाकरण केंद्रों में निशुल्क लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों का टीकाकरण किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया हो, वे अपने मितानिन या फिर नजदीकी शासकीय अस्पताल से संपर्क कर टीकाकरण अवश्य कराएं।

महाशिवरात्रि में दलपत सागर शिवमंदिर

तक जाने चलाया जाएगा दो मोटर बोट

जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय में दलपत सागर के मध्य स्थित भगवान शंकर के मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर इस वर्ष श्रद्धालु दो मोटर बोट के माध्यम से पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना कर सकेंगे। विदित हो कि प्रतिवर्ष दलपत सागर के मध्य स्थित शंकर मंदिर पर एक मोटर बोट के माध्यम से पहुंचकर श्रद्धालु भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते रहे हैं जिससे भारी भीड़ हो जाती थी। इस वर्ष जगदलपुर विधायक किरण देव के पहल पर प्रशासन के द्वारा इस वर्ष दो मोटर बोट चलाया जाएगा।

5 किलो का प्रेशर आईडी बरामद

बीजापुर। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चेरापल कैंप से सीआरपीएफ के जवान सचिंग पर गंगालूर मार्ग की ओर निकली हुई थी। इसी दौरान सीआरपीएफ की बीडीएस की टीम द्वारा डीआईईन के दौरान चेरापल से एक फिलोमीटर आगे गंगालूर मार्ग पर मुख्य सड़क से करीब 70 मीटर के अंदर नक्सलियों द्वारा लगाए गया पांच किलो का प्रेशर आईडी बरामद किया गया और बीडीएस की टीम द्वारा प्रेशर आईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया।

पीएससी भर्ती स्कैम की जांच करेगी सीबीआई साय सरकार ने जारी की अधिसूचना

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने इस केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी है। इस ले कर छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने ईओडब्ल्यू- एसीबी में दर्ज एफआईआर के साथ ही पीएससी घोटाले में दर्ज एक और एफआईआर को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करने की अनुमति भी सीबीआई को दे दी है।

दरअसल, सीजीपीएससी भर्ती घोटाले मामले में राज्य सरकार की ओर से दो एफआईआर दर्ज हैं। एक एफआईआर शासन के निर्देश पर ईओडब्ल्यू-एसीबी में दर्ज कराया गया है। दूसरा एफआईआर बालोद जिले के अजुंजा थाने में दर्ज है। गृह विभाग की ओर से अधिसूचना में दोनों ही मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की जानकारी दी गई है।

जानकारी के मुताबिक तत्कालीन बघेल सरकार के कार्यकाल में सीजीपीएससी के तहत भर्तियों में बड़े पैमाने पर गडबड़ी किए जाने का आरोप लगा है। इस बीच पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित पीएससी के कई अफसरों के खिलाफ इस केस में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। शिकायत के अनुसार पीएससी भर्ती में



गडबड़ी करके सोनवानी सहित अन्य अफसर और नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है। बता दें कि यह मुद्दा विधानसभा चुनाव 2023 में भी छाया था। इसे लेकर भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में ऐलान किया था कि इस केस की जांच सीबीआई से कराएंगे। चूंकि अब प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिज है तो उसने इस घोषणा पर अमल करते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके पहले 3 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही गई थी। अब इसे लेकर साय सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

अम्बेडकर अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय परिसर को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए चलाया अभियान

रायपुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय परिसर को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल, रायपुर एवं अम्बेडकर अस्पताल की टीम द्वारा मंगलवार को अभियान चलाया गया और चालानी कार्यवाही की गई। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) 2003 के अनुपालन में चलाये गये इस अभियान के तहत संयुक्त टीम द्वारा आस-पास के दुकानों एवं टेलों पर चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 22 चालान काटा गया।

इस अवसर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के तम्बाकू नियंत्रण सेल के नोडल ऑफिसर डॉ. विवेक पात्रे ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के

अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय परिसर को तंबाकू मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में यह कार्यवाही की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का क्रय-विक्रय या किसी व्यक्ति द्वारा सेवन किया जाता है तो नोडल अधिकारी द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत चालानी कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है। इस क्रम में परिसर के आस-पास मुक्त शैक्षणिक क्षेत्र एवं तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का बोर्ड एवं जागरूकता के लिए पोस्टर लगाये गए। डॉ. पात्रे ने कहा कि चिकित्सालय परिसर के अंदर किसी भी रूप में तम्बाकू रखना एवं इसका सेवन करना दंडनीय अपराध है। इस दौरान औषधि निरीक्षक परमानंद वर्मा, अजय बैस एवं अम्बेडकर अस्पताल के एच आर मैनेजर राधवेन्द्र साव समेत अन्य उपस्थित थे।

दपूमरे से चलने वाली तीन एक्सप्रेस ट्रेनों के नये स्टॉपेज

यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर छः माह के लिए दिया जा रहा

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मण्डल के अंतर्गत आने वाले शामगढ़ रेलवे स्टेशन में गाड़ी संख्या 20813/20814 पूरी-जोधपुर-पूरी एक्सप्रेस का एवं सुवासरा रेलवे स्टेशन में गाड़ी संख्या 20843/20844 बिलासपुर-भगत की कोटी-बिलासपुर एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव की सुविधा 9 मार्च, से प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मुरेना रेलवे स्टेशन में 12807/12808 विशाखापटनम-निजामुद्दीन-विशाखापटनम एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव की सुविधा 7 मार्च से प्रदान की जा रही है। यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर छः माह के लिए दिया जा रहा है।

10 मार्च, से जोधपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20814 जोधपुर-पूरी एक्सप्रेस का



शामगढ़ रेलवे स्टेशन में 00.33 बजे पहुंचकर 00.35 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में 15 मार्च से पुरी रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20813 पूरी-जोधपुर एक्सप्रेस का शामगढ़ रेलवे स्टेशन में 00.18 बजे पहुंचकर 00.20 बजे रवाना होगी।

9 मार्च से भगत की कोटी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20844 भगत की कोटी-

बिलासपुर एक्सप्रेस का सुवासरा रेलवे स्टेशन में 13.41 बजे पहुंचकर 13.43 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में दिनांक 12 मार्च, 2024 से बिलासपुर रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20843 बिलासपुर-भगत की कोटी एक्सप्रेस का सुवासरा रेलवे स्टेशन में 14.21 बजे पहुंचकर 14.23 बजे रवाना होगी।

5 मार्च से विशाखापटनम से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12807

विशाखापटनम-निजामुद्दीन एक्सप्रेस का मुरेना रेलवे स्टेशन में 13.18 बजे पहुंचकर 13.20 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में 7 मार्च से निजामुद्दीन रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12808 निजामुद्दीन-विशाखापटनम एक्सप्रेस का मुरेना रेलवे स्टेशन में 10.38 बजे पहुंचकर 10.40 बजे रवाना होगी।

11 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान में देरी कांग्रेस पर ना पड़ जाए भारी

रायपुर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम शामिल है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। 11 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, फिर भी कांग्रेस नामों के ऐलान में देरी कर रही है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव भी कहीं कांग्रेस के हाथ से ना निकल जाए। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा का कहना है यह जरूरी नहीं है कि हम भाजपा की कांपी करें। हमारी अपनी रणनीति है। उसके अनुसार नहीं है कि हम भाजपा की कांपी करें। हमें पता है कि किस-किस लोकसभा में किस तरह के उम्मीदवारों का सामना



रूप से चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है, व्यक्ति की छवि का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, जैसे भी कितना समय दे दो, लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी सात आठ विधानसभा क्षेत्र में पहुंच पाना किसी भी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं होता है। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव, मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। और मुद्दों की कमी हमारे पास नहीं है। भाजपा ने जिस तरह से वादा खिलाफी की है। रेलवे में

सीनियर सिटीजन की सुविधा खत्म कर दी गई है। केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की बात करती है लेकिन यहां पैसेंजर ट्रेन भी बंद है। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये हो गया है। बैंक से पैसा निकालने और जमा करने दोनों समय पैसा कट रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेरोजगारी चरम पर है। विदेशी धन कितना आया आज तक बताया नहीं गया है। नोटबंदी में कितना फायदा है उसका पता नहीं चला। इन सारे मुद्दों के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उसी आधार पर इस बार हम भाजपा को कड़ी चुनौती देंगे। सुरेंद्र शर्मा ने कहा भाजपा को जो गुड़ फील है वह बेड फील होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे मोहब्बत पसंद नहीं होगी। नफरत फैलाने वाले लोगों के अलावा हर आदमी चाहता है कि देश में शांति रहे सभी मिलजुल कर रहे। किसी

भी जाति, धर्म, समुदाय, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा ही क्यों ना हो, सबको एक साथ करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। उसका आशा है। लोकसभा चुनाव में चुनौती

पर सुरेंद्र शर्मा ने कहा लोकसभा चुनाव में भाजपा एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि बीजेपी छलबल में बहुत माहिर है। उसका मुकाबला हमको करना है।

Government of Chhattisgarh Water Resources Department OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER MAHANADI CIRCLE, RAIPUR (CHHATTISGARH)		
CORRECTION NO. - I		
In System Tender No. 152798, N.I.T. No. 36/SAC/2023-24, Raipur Dated: 13.02.2024 whose G-Number is 07834 Dtd. 15.02.2024, following amendments are made :-		
S. No	Earlier Published	Amendments Now Read as
1	Online Tenders are invited for the following works up to 01.03.2024 at 17.30 Hours	Online Tenders are invited for the following works up to 11.03.2024 at 17.30 Hours
2	Bid Open Start Date and time: 04.03.2024, 11:30 Hours	Bid Open Start Date and time: 12.03.2024, 11:30 Hours
Note:- All other terms and conditions will remain be unchanged.		
Executive Engineer Water Management Division No. 1, Raipur For, Superintending Engineer Mahanadi Circle, Raipur (C.G.)		
G- 08274/8		

सुप्रीम फैसलों ने बढ़ाया देश का मान, न्यायपालिका पर विश्वास

रमेश सर्राफ धमोरा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कई ऐसे फैसले दिए हैं जिससे देश का मान तो बढ़ा ही है। उसके साथ ही वो फैसले न्यायपालिका के क्षेत्र में भी मील के पत्थर साबित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से जहां हर देशवासी को गौरवान्वित किया हैं। वहीं देशवासियों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास को भी सुदृढ़ किया है। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की पूरे देश में सराहना हो रही है। देश के आम आदमी को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह महसूस होने लगा कि हमारे देश में न्याय कभी कमजोर नहीं हो सकता है। हालांकि पिछले कई वर्षों से देश में न्यायपालिका को कमजोर करने के आरोप लग रहे थे। जिनको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने झूठला दिया है। 04 मार्च 2024 को वोट के बदले नोट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने सोमवार को अपना 25 साल पुराना फैसला पलट दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं हैं। जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। 1998 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3–2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। यह मायने नहीं रखता है कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद घूस स्वीकार करता है। संविधान के आर्टिकल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार-विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए हैं। दोनों अनुच्छेद का मकसद तब बेमानी हो जाता है। जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट हासिल नहीं है। रिश्वत लेने वाला अपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। यह मुद्दा दोबारा तब उठे जब झामुमो विधायक सीता सोरेन ने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिक दाखिल की। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2012 के झारखंड के राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। सीता सोरेन ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि उन्हें सदन में कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के तहत छूट हासिल है। इसी तरह कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए राजनीतिक दलों के लिए चंदा जुटाने की पुरानी इलेक्टोरल बांड स्कीम को अवैध करार देते हुए इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बांड की गोपनीयता बनाए रखना अवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में गठित पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वह प्रक्रिया है जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। याचिकाकर्ताओं ने इस योजना को लागू करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2017 और फाइनेंस एक्ट 2016 में किए गए कई संशोधन को गलत बताया था।

ज्ञान/मीमांसा

परिवार प्रथम या राष्ट्र प्रथम

अजय सेतिया

इंडी एलायंस बनने के नौ महीने बाद उसी पटना में पहली रैली हुई, जहां एलायंस की पहली बैठक हुई थी। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि एलायंस की पहली बैठक बुलाने वाले नीतीश कुमार रैली में निशाने पर थे, क्योंकि वह एनडीए में वापस लौट चुके हैं। रैली में इंडी एलायंस के 31 में से सिर्फ चार दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जिससे इंडी एलायंस की एकता का मेसेज नहीं जा सका क्योंकि एलायंस में शामिल दलों के मुख्यमंत्रियों अरविन्द केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्तलिन, पिनयारी विजयन और चंपई सोरेन में से कोई भी शामिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्रियों में से भी कोई नहीं पहुंचा। इसलिए रैली सिर्फ आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियों का जमावड़ा बन कर रह गई, जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी. राजा शामिल हुए।

लालू यादव बड़ी बड़ी रैलियां करने के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की यह रैली उन रैलियों के मुकाबले की नहीं थी। भाषण तो सबके हुए, लेकिन अपने पुराने स्टাইल से भाषण देकर सारी वाहवाही लालू यादव ने लूट ली, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने उनके हिन्दू होने पर ही सवाल उठा दिया। लालू यादव ने एक तो यह कहा कि जब मोदी की मां का देहांत हुआ तो उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई, और सिर नहीं मुंडवाया। दूसरा उन्होंने कहा कि उनकी मां के देहांत के बाद उनका परिवार ही नहीं है। पता नहीं इन दोनों ही बातों का राजनीति से क्या संबंध है। न उनकी इस बात का चुनाव पर कोई असर होगा, क्योंकि जातिवाद की राजनीति करके हिन्दुओं को अमड़ा पिछड़ों में विभाजित करने वाले लालू यादव के कहने पर हिन्दू प्रभावित नहीं होने वाले। लालू यादव खुद कितने समर्पित हिन्दू हैं, यह भी सब जानते हैं। उन्हीं की पार्टी के शिक्षा मंत्री चन्द्रशेखर जब आएं दिन रामचरित मास पर सवाल उठा रहे थे, तो वह चुप्पी साध कर बैठे थे।

इसके अलावा लालू यादव ने मोदी का परिवार नहीं होने की बात कह कर सेल्फ गोल



कर लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पिछले एक दशक से परिवारवाद की राजनीति पर ही हमला बोल रहे हैं। वह तो शुरू से ही कहते रहे हैं कि उन्हें कोई मोह नहीं है, वह तो झोला उड़ाएंगे और चले जाएंगे। यह एक आम धारणा है कि नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है, जिसके लिए वह भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियां भरें। मोदी ने तेलंगाना में अपने भाषण में कहा भी कि जिसका परिवार होता है, क्या उसे भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल जाता है। लालू यादव का यह कहना कि नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के देहांत के बाद सिर नहीं मुंडवाया, इसलिए वह हिन्दू नहीं हैं, यह बहुत ही गलत किस्म की टिप्पणी है, जिसे कोई भी हिन्दू पसंद नहीं करेगा। मुंडन को लेकर हर जगह अलग अलग परंपरा है, परिवार में किसी की मौत पर कहीं कहीं घर के सभी पुरुष बाल कटवाते हैं, तो कहीं कहीं परिवार का एक ही सदस्य सिर मुंडवाता है।

वैसे भी नरेंद्र मोदी सन्यास की दहलीज से वापस लौटे हैं। जब से वह सन्यास की दहलीज से वापस लौटे हैं, तबसे समाज क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे देश वासियों को अपना परिवार मानते रहे हैं। उनकी परिवार की परिभाषा को देश लालू यादव से बेहतर जानता है। मोदी हर साल सीमा पर देश की रक्षा कर रहे जवानों के साथ

दिवाली मना कर बताते हैं कि उनका परिवार कौन है। लालू यादव की ये दोनों ही अराजनैतिक बातें क्या मोदी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में कोई संवैधानिक अड़चन पैदा करती हैं। मंच पर बैठे कम्युनिस्ट और अन्य विपक्षी नेता लालू को इस बात पर खिलखिला कर हंसे, कुछ ने तालियाँ भी बजाईं। जिससे स्पष्ट होता है कि इंडी एलायंस में चुनाव को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। याद कीजिए पिछले चुनाव में जब राहुल गांधी चौकीदार चोर का नारा लगवा रहे थे, तब सारे देश में क्या मुहिम चली थी। करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं भी चौकीदार। ठीक उसी तरह अब सोशल मीडिया पर हर कोई मोदी को अपने परिवार का हिस्सा बता रहा है।

इस मुहिम ने विपक्ष के नेताओं को नई मुश्किल में डाल दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस मुहिम का कैसे जवाब दें। अखिलेश यादव ने सारे देश में चल रही मुहिम का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि ऐसा लगता है, जैसे मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। जयराम रमेश की प्रतिक्रिया से साफ जाहिर हुआ कि कांग्रेस देश में मोदी के परिवार को लेकर चली मुहिम से हताश है। विपक्ष हर चुनाव से पहले कोई न कोई ऐसी गलती करता है कि चुनाव उसके हाथ से निकल जाता है। पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-24)

गतांक से आगे...

सिर का काटा जाना, सुखप्रदायिनी निद्रा के समान; (जिह्वा आदि काटकर) गूंगा हो जाना, मौनवालम्बन के समान; बर्हिर् हो जाना, उजति के समान सुख प्रदायी होता है; लेकिन वह अवस्था उपेक्षा करने से नहीं मिलती। इसकी प्राप्ति दृढ़निश्चयी होकर वैराग्यजनित आत्मज्ञान से ही सम्भव है। गुरु एवं शास्त्र वचनों के अनुराध तथा अन्तः अनुभूति के माध्यम आदि से जो अन्तः की शुद्धि होती है, उसी के सतत अभ्यास से आत्म-साक्षात्कार किया जा सकता है।

जैसे दिशा-भ्रम नष्ट हो जाने से पूर्व की भाँति ही दिशाबोध होने लगता है, वैसे ही विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाने पर जगत् की स्थिति नहीं रहती, ऐसी भावना करनी चाहिए। मनुष्य का उपकार न धन से,न मित्रों से, न बान्धवों से; न शारीरिक क्लेश के नष्ट होने से और न ही तीर्थ स्थल



में निवास करने से ही मनुष्य लाभान्वित होता है; वह तो चिन्मात्र में विलीन होकर ही परमपद प्राप्त कर सकता है।

स्थिर शान्तचित्त वाले व्यक्तियों के जितने भी दुःख, तृष्णायें एवं दुःसह दुश्चिन्तार्यें हैं, वे और समस्त विकार ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणों से अन्धकार विनष्ट हो जाता है। इस नश्वर जगत् में शम (मनोनिग्रह) से युक्त मनुष्य का कठोर एवं मुदु स्वभाव के समस्त प्राणी-जन वैसे ही विश्वास करते हैं, जैसा माता पर उसके पुत्र विश्वास करते हैं। अमृत-पान एवं लक्ष्मी के आलिङ्गन से वैसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा सुख व्यक्ति अपने मन की शान्ति से प्राप्त करता है। शुभ एवं अशुभ के श्रवण से, भोजन से, स्पर्श से, दर्शन से एवं जानने से, जिस मनुष्य को न तो प्रसन्नता होती है और न ही दुःख होता है, वही मनुष्य शान्त कहलाता है।

क़मशः ...

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत

प्रदीप कुमार सिंह

पंत जी का जन्म 18 सितम्बर 1857 में गांव खूंट, अल्मोड़ा उत्तराखंड (जोकि पहले उ.प्र.) में हुआ था। वह महाराष्ट्रियन मूल के थे। मां का नाम श्रीमती गोविन्द बाई था। माता के नाम से ही उनको गोविन्द नाम मिला था। भारत रत्न पं. गोविन्द बल्लभ पंत जी आधुनिक उत्तर भारत के निर्माता के रूप में याद किये जाते हैं। वह देश भर में सबसे अधिक हिन्दी प्रेमी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 4 मार्च, 1925 को जनभाषा के रूप में हिन्दी को शिक्षा और कामकाज का माध्यम बनाने की जोरदार मांग उठाई थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र भाषा के बिना देश गूंगा है। मैं हिन्दी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता किन्तु उनके साथ हिन्दी को भी मिला देना चाहता हूँ। पंत जी के प्रयासों से



और विकास को कोई रोक नहीं सकता। हिन्दी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। विदित हो कि पंत जी के जन्म के चौथे दिन 14 सितम्बर को देश भर में हिन्दी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही हिन्दी को विश्वव्यापी पहचाने दिलाने के लिए 10 जनवरी को अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन ने हिन्दी को राजभाषा और देवनागरी को राजलिपि के रूप में स्वीकृत कराने में बड़ी भूमिका

निभायी है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेई जी ने भी हिन्दी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। अटल जी ने वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार में हिन्दी मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश में भाषण देकर इतिहास रचा था। वैश्विक बिरादरी ने इस ऐतिहासिक हिन्दी भाषण तथा करोड़ों भारतीयों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया था।

पंत जी ने राजकीय सेवा की पारिवारिक परम्परा से हट कर देश सेवा के लिए अपने सम्पूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया था। वे प्रखर वक्ता, नैतिक तथा चार्ित्रिक मूल्यों के उत्कृष्ट राजनेता, प्रभावी सांसद और कुशल प्रशासक थे। जर्मंदारी उन्मूलन उनकी सुरक्षा का साहसिक निर्णय था जिससे लाखों किसानों का भाग्य बदल गया और वे उस जमीन के मालिक बन गए जिस पर हाड़तोड़ मेहनत करने के

बाद भी उनका कोई अधिकार नहीं था। निर्बलों के कल्याण, कमजोर को आर्थिक, सामाजिक न्याय और प्रदेश में नियोजित विकास की नींव रखने के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा।

इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 7 मार्च, 1961 को देहान्त हो गया। महापुरुष सदैव अपने लोक कल्याण के कार्यों के कारण अमर रहते हैं। आत्मा अजर अमर तथा अविनाशी है। आज वह देह रूप में हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके उच्च नैतिक विचार, सेवा भावना, सादगी, सहजता, हिन्दी प्रेम तथा उज्वल चरित्र देशवासियों का युगों-युगों तक मार्गदर्शन करत रहेगा। हम इस महान माता और जय श्रीराम पर घोर आपत्तिजनक टिप्पणियां करके मोदी और भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्र फर्स्ट के मुद्दे को और मजबूत कर दिया है।

आज का इतिहास

- 1969 इसरायल ने 70 साल की गोल्डा मेयर को प्रधानमंत्री चुना था।
- 1985 एड्स का पहला एंटीबाइड परीक्षण एलिसा-टाइप टेस्ट शुरू किया गया।
- 1985 अफ्रीका के लिए सुपररूप यूएसए द्वारा चैरिटी सिंगल वी आर द वर्ल्ड जारी की गई थी, और इसकी 20 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकेंगी।
- 1992 माइकोल स्टीवेन्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक समय में 200 मीटर की तैराकी में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का कारनामा किया (2:06:78)
- 1993 टोड ब्रिज, प्रसिद्ध अभिनेता, एक किरायेदार को छुरा घोंपने के लिए गिरफ्तार किया गया है।
- 1994 8 वें अमेरिकी कॉमेडी अवार्ड की घोषणा की गई है। गाजर टॉप विजयता बनता है।
- 1994 लाइबेरिया के राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
- 1995 डॉलर, 1.5330 इच गिल्टर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।
- 1995 मौत की सजा देने वाला न्यूयॉर्क दुनिया का 38 वां राज्य है।
- 2009 नासा ने ब्रम्हांड में पृथ्वी जैसे ग्रह और उनपर जीवन को तलाशने के लिए केप कनावेरल से केप्लर नाम की एक दूरबीन को अंतरिक्ष में छोड़ा था।
- 2009 केप्लर अंतरिक्ष वेधशाला, जिसे पृथ्वी-जैसे किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करने के लिए डिज़ाइन किया गया, लॉन्च किया गया।
- 2009 ब्रिटिश सेना की 38 इंजीनियर रेजिमेंट के दो ऑफ-इयूटी सैनिकों को उत्तरी आयरलैंड के एंटीम शहर में रियल ड्रुम्स द्वारा गोली मार दी गई थी।
- 2010 82 वें अकादमी पुरस्कार: हर्ट लॉकर, जेफ ब्रिन्स और सैंड्रा बुलोक ने जीता।
- 2010 इराकी मतदाताओं ने संसदीय चुनाव में भाग लिया था।
- 2011 पाब्लो पिकासो द्वारा बनाई गई न्यूड, ग्रीन लीव्स एंड बस्ट नाम की दुनिया में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग लंदन की टेट गैलरी में प्रदर्शित की गई।
- 2012 एयरलाइन उड़ानें जीपीएस सिस्टम और पावर ग्रिड को सबसे बढ़ा सौर भड़कना, पृथ्वी के पास से परेशान किया जाएगा, जो पांच साल में होता है, 6 मार्च 2012 को घटित होगा।
- 2014 एक अध्ययन ने आज घोषणा की है कि रक्त में विटामिन डी का उच्च स्तर स्तन कैंसर के रोगियों के लिए जीवित रहने की संभावना को बढ़ा सकता है और इसलिए लोगों को जीवित रहने के लिए एक आशा देता है।

क्या मायावती अपनी पार्टी को खत्म करने पर तुली हैं?

अजय कुमार

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी कुछ राजनैतिक जिम्मेदारियां अपने भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंप कर क्या संदेश दिया है, कोई नहीं जानता। मायावती ने अपने आप को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक समेट कर बाकी राज्यों की जिम्मेदारी आनंद को दे दी है। मायावती के इस फैसले पर नेतागण अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ को लगता है कि मायावती ने काफी सोच समझकर बसपा में अपने आप को सीमित किया है। संभवतः वह नहीं चाहती होंगी कि देश जीतने के चक्रर में कहीं उनका मजबूत किला यूपी और उत्तराखंड हाथ से नहीं निकल जाये। जहां उनके लिये हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। कहा यह जा रहा है कि बहनजी चुनाव की तारीख घोषित होते ही यूपी में अपनी जनसभाएं शुरू कर देंगी। पहले वह मंडलवार सभाएं करेंगी। बीएसपी के लिये मजबूत समझी जाने वाली सीटों पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा। मजबूत समझी जाने वाली सीटों के लिये वह जनसभाएं भी ज्यादा करेंगी।

चुनाव की बेला में मायावती ने जो कदम उठाया है उससे बसपा को कितना नफा-नुकसान होगा यह तो समय ही बतायेगा, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो ने जो भी फैसला लिया है, वह काफी सोच समझकर लिया होगा। मायावती एक परिष्क नेत्री हैं। उन्होंने बसपा को इस बुलंदी तक पहुंचाने में पूरा योगदान दिया था। दलित चिंतक स्वर्गीय काशीराम को राजनैतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली मायावती की पहचान एक बड़ी नेत्री के रूप में होती है। मायावती पर दलित पूरा विश्वास करते हैं। दलित वोटरों ने कभी भी बहनजी का साथ नहीं छोड़ा जबकि मायावती अपनी सियासी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर गैर दलित वोटरों को भी बसपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती रही। बसपा की सियासी प्रयोगशाला से मायावती ने कभी दलित-मुस्लिमों को एक छतरी के नीचे खड़ा किया तो कभी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की राजनीति को अमली जामा पहनाया। मायावती ने दलित नेताओं की बड़ी लीडरशिप तैयार की तो कई क्षत्रिय,

ब्राह्मण, पिछड़ों और मुस्लिम चेहरों को भी राजनीति में उभरने का पूरा मौका दिया, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी रहा कि बसपा सुप्रीमो ने भले ही नये नेताओं की ‘फौज’ तैयार की थी, लेकिन यह नेता मायावती के साथ लम्बे समय तक रह नहीं पाये। इसमें से ज्यादातर को बहनजी ने स्वयं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था तो कुछ ने मौके की नजाकत को भांप कर स्वयं पार्टी छोड़ने में देरी नहीं की। वैसे यह यह बताना भी गलत नहीं होगा कि मान्यवर कांशीराम ने सिर्फ मायावती को ही आगे नहीं बढ़ाया था। अलग-अलग समाज के लोगों को चुनकर उन्हें नेता बनाया था। ओमप्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल, आरके चौधरी और मसूद अहमद ऐसे ही नेताओं में शामिल रहे हैं लेकिन सभी बिछड़ते गए। राजभर ने 2002 में, दिवांगत सोनेलाल पटेल ने 1995 में और आरके चौधरी ने 2016 में बसपा छोड़ दी थी। आरके चौधरी तो राजनीति में कोई जगह हासिल नहीं कर पाए लेकिन ओमप्रकाश राजभर और सोने लाल पटेल की पार्टी आज भी अच्छी खासी राजनीतिक ताकत रखती हैं।

बसपा को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाने वाली मायावती की राजनीति पिछले दस वर्षों से काफी उतार पर नजर आ रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में वह अंतिम बार बड़े अंतर से सपा से जीती थीं। आज की तारीख में बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी के कई दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। इनमें कई ऐसे भी नाम हैं, जिन्हें एक समय मायावती का सबसे करीबी नेता माना जाता था। इनमें लालजी वर्मा न सिर्फ विधानमंडल दल के नेता थे बल्कि वर्मा वह नेता हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष रहते 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनी थी। राम अचल राजभर भी मायावती के खासम खास माने जाते रहे हैं। 13 सालों में बसपा 206 विधायकों से महज एक विधायक पर आ टिकी है। बसपा के जिन नेताओं को प्रदेश स्तर पर पहचान हासिल हुई थी वह एक-एक करके बसपा से अलग हो गए हैं। 2007 में जब प्रदेश में बसपा की बहुमत की सरकार बनी थी तब मायावती ने जितने विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया था, उनमें से आज एका-दुक्का ही बसपा के साथ खड़े हैं। 2007 में 206



सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती ने नकुल दुवे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामवीर उपाध्याय, ठाकुर जयवीर सिंह, सुधीर गोयल, स्वामी प्रसाद मौर्य, वेदराम भाटी, चौधरी लक्ष्मी नारायण, राकेश धर त्रिपाठी, बाबू सिंह कुशवाहा, फागू चौहान, दहू प्रसाद, राम प्रसाद चौधरी, धर्म सिंह सैनी, राम अचल राजभर, सुखदेव राजभर और इंद्रजीत सरोज को बड़े पोर्टफोलियो दिए थे, लेकिन आज इसमें से कोई भी बसपा में नहीं है। सबने अपनी अलग राह पकड़ ली है।

2012 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। उसके पश्चात 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए। 2022 में भी उनको जीत हासिल हुई और एक बार फिर वह सीएम बने। लेकिन मायावती का कहीं से कोई भला नहीं हुआ। 2007 में चुनाव जीतकर सरकार बनाने के बाद से उनकी सत्ता में वापसी भी नहीं हुई है जबकि अपनी ताकत बढ़ाने के लिये मायावती ने 2019 में अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी तक से हाथ मिला लिया। परिणाम स्वूपर उनके दस सांसद चुनाव जीते थे, लेकिन अब यह सांसद भी बसपा से दूरी बनाने लगे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा, पार्टी बदलना मेरे लिए समय की जरूरत थी। मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गया हूं और अब यह मेरा कर्तव्य है कि पार्टी को मजबूत करूँ

राजनीति और अपराध का खतरनाक गठजोड़

अमेश चतुर्वेदी

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद इसे सिर्फ आपराधिक मामले की तरह देखे-सुने जाने की कोशिश होगी। लेकिन शाहजहां शेख का मामला सिर्फ आपराधिक नहीं है, बल्कि यह राजनीति के अपराधीकरण की समस्या की ओर भी ध्यान दिलाता है। समूचे देश के छोटे राजनीतिक दलों की ओर नजर दौड़ाइए, अपराध और राजनीति का गठजोड़ जितना वहां सहज तरीके से दिखेगा, वैसे नजारा भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों में कम ही दिखता है। छोटे दलों वाली राजनीति अपराधियों के स्थानीय रसूख के दम पर समर्थन हासिल करती है, इसी समर्थन के दम पर वह संवैधानिक ताकत हासिल करती है एवं फिर वह अपने क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि और राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित हो जाती है। चूंकि इस प्रक्रिया में अपराधी सबसे बड़ा औजार बन राजनीतिक दल के साथ खड़ा रहता है, इसलिए वह बदले में ताकत, पद आदि भी हासिल करने की कोशिश करता है। बिहार के शहाबुद्दीन रहे हों या मुनील तिवारी या उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद, उन्हें छोटे और स्थानीय दल रास आते रहे। राजनीतिक छतरी में उनका कारोबार फलता-फूलता रहा।

साठ-सतर के दशक तक अपराधी राजनीति को बूथ लूटने, वोटरों को धमकाने, उन्हें प्रकारांतर से समझाने के काम आते रहे। बदले में वे कुछ ठेके और आर्थिक फायदे ही हासिल करते रहे। बाद में जब अपराधियों को लगने लगा कि जब उनके दम पर पार्टी संवैधानिक पद हासिल कर सकती है, चुनाव जीत सकती है, तो वे खुद सीधे क्यों नहीं राजनीति में आ सकते। इसके बाद बिहार में सूरजदेव सिंह, काली पांडे, सूरजभान, शहाबुद्दीन जैसे लोग उभरे। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, हरिशंकर



तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही, धनंजय सिंह जैसी राजनीतिक ताकतें उभरीं। अंध प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम जगहों पर ऐसे अपराधियों की

लंबी सूची बन गयी। वामपंथी दलों का दावा रहा है कि वे नैतिकता की राजनीति कुछ ज्यादा ही गहराई से करते रहे हैं। भारतीय राजनीति के लोकवृत्त यानी पब्लिक स्फ़ीयर में जो मूल्य स्थापित हुए हैं, उनमें से ज्यादातर की सूत्रधार वामपंथी राजनीति रही है। लेकिन इसी राजनीति का स्याह पक्ष पश्चिम बंगाल की राजनीति भी रही है, जहां की राजनीति में एक दौर में अपराधियों का बोलबाला था, जिन्हें वाममोर्चा की सत्ता की छॉव मिलती रही। जिसने भी वामपंथी राजनीति के इस भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर सवाल उठाने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। मारपीट तो बंगाल की राजनीति का स्थायी भाव रही। ममता बनर्जी ने इस पर लगाम लगाने का वादा जरूर किया, लेकिन जब उसे पूरा करने का वक आया, तो वे भी बदलने लगे। यही वजह है कि वहां शाहजहां शेख जैसे नेता उभरने लगे।

राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ पर पहली बार 1993 में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव एएन वोहरा समिति ने विचार किया था। लेकिन उस रिपोर्ट पर किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में उस रिपोर्ट को जांच एजेंसियों को देने की मांग को लेकर 2000 में याचिका डाली गयी। पर सुप्रीम कोर्ट इस मांग को पूरा नहीं कर

पाया। इस रिपोर्ट को अब तक सर्वजनिक तक नहीं किया गया है। वह तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, कि उसने चुनावों में उम्मीदवारों के लिए अप्रनी और अपने पति या पत्नी की संपत्ति की घोषणा करना और अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों का हलफनामा जमा करना जरूरी बना दिया। बेशक जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी सांसद की सांसदी और विधायक की विधायकी तभी खत्म होती है, जब जन प्रतिनिधि को तीन साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है। इसे कानून की खामी ही कहेंगे कि अपराधी कहे जाने लोग भी चुनाव लड़ जाते हैं और कई बार उसकी राबिन्हुड़ी छवि, तो कई बार खराब सम्मान में उन्हें अपना समर्थन दे डालते हैं। राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद वह आपराधिक व्यक्ति जैसे गंगा में नहा उठता है।

हमारा समाज भी ऐसा है कि अतीत में जिसे सजा हो चुकी होती है, यदि वह जोड़तोड़ से कोई पद हासिल कर लेता है, उसे दुनिया अपनी नजरों पर उठा लेती है। राजनीति तो हमेशा समर्थन के लिए लालायित रहती है, इसीलिए वह अपराधियों को खुद से दूर नहीं करना चाहती। लेकिन जब उस आपराधिक व्यक्ति के चलते राजनीति की अपनी दुनिया प्रभावित होने लगती है, तो उससे पीछे छुड़ने और उससे अपना रिश्ता तक दिखाने से राजनीति भाग खड़ी होती है। यह सब वह पापमुक्त होने के लिए करती है। शाहजहां शेख को तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता से बर्खास्त किया जाना राजनीति की उसी रव्यात का एक उदाहरण है। शाहजहां शेख के मामले ने राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती छोड़ी है कि क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं हो सकता, जो 22 कैरट टोस नैतिकता की राजनीति करे, अपराधियों को किसी भी कीमत पर खुद से दूर रख सके और राजनीति को साफ-सुथरा रखने के लिए खुद और अपने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा रखे। फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है।

परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार की लड़ाई में आगे कौन ?

अकि्त सिंह

परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए भाजपा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी दलों पर निशाना साधते रहते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी के बाद विपक्ष को भाजपा और मोदी पर पलटवार करने का मौका मिल गया है। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं। भाजपा ने पार्टी के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि हमारी पार्टी कैडर आधारित है जो उम्मीदवारों के चेहरे पर नहीं बल्कि कैडर की ताकत पर चुनाव लड़ती है। हालांकि, विपक्ष इसे धुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये सब तब हो रहा है कि मोदी के परिवार पर लालू यादव के एक बयान में राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है।

पीएम मोदी अक्सर वंशवाद की राजनीति पर वार करते रहते हैं। वहीं, विपक्ष का दावा रहता है कि भाजपा में भी परिवारवाद है। विपक्ष का दवा रहता है कि राजनाथ सिंह और उनके बेटे एक साथ राजनीति में हैं। राजनाथ सिंह जहां सांसद और रक्षा मंत्री हैं तो वहीं उनके बेटे पंकज सिंह नौएडा से विधायक हैं। इसके अलावा विपक्ष नारायण राणे का भी नाम लेता है जो केंद्र में मंत्री हैं उनके बेटे नितिश राणे भाजपा के विधायक है। विपक्ष की ओर से धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का भी नाम लिया जाता है। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल और मां चंद्रकांता गोयल भी भाजपा से जुड़ी रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पिता देबेंद्र प्रधान भी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष का दावा रहता है कि अगर मोदी और भाजपा को परिवारवाद से दिक्कत है तो उसने ऐसी पार्टियों से गठबंधन क्यों किया है जिनमें परिवारवाद हावी है। इसको लेकर विपक्ष की ओर से जीतन राम मांझी की पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी का हवाला दिया जाता है।



हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि एक परिवार को कई पीढ़ियों के सदस्य यदि योग्यता से राजनीति में आते हैं तो वह उसे परिवारवाद नहीं मानते बल्कि एक ही परिवार द्वारा पार्टी चलाने को गलत मानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक परिवार के आगे कुछ नहीं दिखाई देता और इससे उसने खुद का, विपक्ष का, देश का और संसद का बड़ा नुकसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि देश को अच्छे, स्वस्थ विपक्ष की बहुत जरूरत है, लेकिन कांग्रेस ने दस साल के बाद भी स्वस्थ विपक्ष बनने का प्रयास नहीं किया। मोदी ने परिवारवाद को लेकर भाजपा से बयानों पर आने वाली प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए कहा, “आज मैं परिवारवाद का मतलब समझा देता हूं। अगर किसी परिवार के एक से अधिक लोग जन समर्थन से अपने बलबूते राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो उसे हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा।” उन्होंने कहा, “हम किसी पार्टी को एक ही परिवार द्वारा चलाये जाने, परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता मिलने, परिवार के लोगों द्वारा ही सारे निर्णय लिये जाने को परिवारवाद मानते हैं।” मोदी ने सदन में सत्ता पक्ष की अग्रिम पंक्ति में अपने पास बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की ओर इशारा करते हुए कहा, “न राजनाथ जी का कोई राजनीतिक दल है, न अमित शाह का कोई राजनीतिक दल है।” विपक्ष पर वार करते हुए मोदी

बार-बार कह रहे कि वो कहते हैं – परिवार फर्स्ट, मोदी कहता है –राष्ट्र फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार भी सबकुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सबकुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देशहित को बलि चढ़ा दिया। मैंने देशहित के लिए खुद को खपा दिया है। नरेन्द्र मोदी की ओर से पूरे देश को अपना परिवार बनाए जाने के कुछ देर बाद सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के ‘प्रोफाइल’ पर अपने नाम के आगे ‘मोदी का परिवार’ लिखा और इस संबंध में एक अभियान शुरु कर दिया। एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पटना में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी पर ‘अपना परिवार’ नहीं होने को लेकर कटाक्ष किया था। इसके बाद भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में यह अभियान चलाया। लालू ने एक रैली में कहा था, “अगर नरेन्द्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वह राम मंदिर के बारे में डींगें मारते रहते हैं। वह सच्चे हिंदू भी नहीं हैं। हिंदू परंपरा में बेटे को अपने माता-पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुंडवानी चाहिए। जब मोदी की मां की मृत्यु हुई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए हाल में ही कहा था कि ‘इंडिया’ गठबंधन सभी वंशवादी पार्टियों का गठबंधन है। सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सीएम बन जाएं। लालू यादव का मकसद भी अपने बेटे को सीएम बनाना है। इसी तरह से एमके स्टालिन भी चाहते हैं कि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के सीएम बनें। मुलायल सिंह तो अपने बेटे को सीएम बनाकर ही गए हैं।

कांग्रेस नेता का दावा, अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे, जिस निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने पहले 2002 से कई बार प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में दिल्ली में एक बैठक से लौटे कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने पुष्टि की कि राहुल गांधी अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। 1967 में उत्तर प्रदेश के गठन के बाद से ही अमेठी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी में परिवार के राजनीतिक गढ़ पर कब्जा कर लिया और 2009 और 2014 में फिर से चुने गए। गांधी ने 2002 से 2019 तक संसद में अमेठी का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि, उन्हें केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। 2019 के आम चुनाव में ईरानी ने राहुल को उनके गढ़ में 55,120 वोटों से हराया था।



संदेशखाली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को झटका

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है। बुधवार (6 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। यह मामला संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जल्द सुनवाई की जरूरत इसलिए है, क्योंकि वे इस आदेश को रोकना चाहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के पास लेकर जाएं। वही इस केस को लिस्ट करेंगे।

शेख शाहजहाँ मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई

कोलकाता। निर्लांबित टीएमसी नेता शेख शाहजहाँ को हिरासत में नहीं सौंपने पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सीबीआई ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। जांच एजेंसी ने तत्काल सुनवाई की मांग की है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब सीबीआई ने दावा किया कि बंगाल सीआईडी ने शेख शाहजहाँ को मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक जांच एजेंसी को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस को पूरी तरह से पक्षपाती कहा और आदेश दिया कि जनवरी में संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाए। हालांकि, बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने यह कहते हुए शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया कि मामला अदालत में है।

सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी

नई दिल्ली। सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद सांसद नवीन राणा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले में औबेसी पर आरोप लगाया है। धमकी मामले में सांसद औबेसी की भी जांच होनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। औबेसी और धमकी के बीच क्या संबंध है, यह जल्द ही सामने आ जाएगा। लोकसभा में सांसद औबेसी और नवनीत राणा के बीच बहस हो गई। अक्सर हमें औबेसी के कार्यकर्ताओं से धमकियां मिलती रहती हैं। इसलिए नवनीत राणा ने इस बात की भी जांच करने की मांग की है कि क्या इस बार भी इनके बीच कोई कनेक्शन है। मुझे जो धमकी मिली वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आई थी। इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम लिया गया है। मेरी रश्मि शुक्ला से बात हुई है, एटीएस जांच कर रही है। गृह विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि देश को बम से उड़ाने की धमकी किसने दी। केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए।

आप के प्रस्ताव पर सस्पेंड सात विधायकों का निलंबन रद्द

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अधिभाषण को बाधित करने के लिए विधानसभा से सात भाजपा विधायकों के निलंबन को बुधवार को रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात विधायकों- मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जीतेन्द्र शर्मा और विजेन्द्र गुप्ता ने पिछले महीने अदालत का रुख किया और विधानसभा से उनके निलंबन को चुनौती दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश सुनाते हुए कहा कि रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। विधायकों ने तर्क दिया था कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के समापन तक उनका निलंबन लागू नियमों का उल्लंघन था। दूसरी ओर, विधानसभा अधिकारियों ने अदालत को आश्वासन दिया था कि विधायकों का निलंबन सदन में असंतोष को दबाने का प्रयास नहीं था।

बंगाल में बोले प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार की वापसी पक्की, उड़ी हुई है विपक्षी नेताओं की नींद

टीएमसी सरकार गुनहगारों को बचा रही है : मोदी

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला रैली को संबोधित करने पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बारासात पहुंचे। इस दौरान उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय, जय मां काली और जय मां दुर्गा के जयकारे के साथ की। उन्होंने संदेशखाली मामले में ममता बनर्जी की सरकार को जमकर घेरा।



गवाह है कि भाजपा सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 वर्षों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किमी रूट बना था, जबकि भाजपा सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किमी और विस्तार हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल और देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता, बहन कह रही है - अबकी बार एनडीए सरकार 400 पर!

उन्होंने कहा कि बंगाल की ये भूमि नारीशक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है, यहां से नारीशक्ति ने देश को दिशा दी है। इस धरती ने अनेक शक्ति स्वरूपा इस देश को दी है, लेकिन इसी धरती पर तुणमूल कांग्रेस के राज में नारीशक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेशखाली को कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को, आपके बुद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनाहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन उन्हें पहले हाइकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है।

उन्होंने कहा कि आज का ये विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्ष्य है कि भाजपा कैसे नारीशक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश में नारीशक्ति वंदन अभियान शुरू किया था, इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया। आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि आज का ये विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्ष्य है कि भाजपा कैसे नारीशक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश में नारीशक्ति वंदन अभियान शुरू किया था, इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया। आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी परिवारों की बहन-बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह-जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन-बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। नारीशक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेशखाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। तुष्टिकरण और टोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुर्खा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार और रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सकें, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि आज का ये विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्ष्य है कि भाजपा कैसे नारीशक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश में नारीशक्ति वंदन अभियान शुरू किया था, इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया। आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि आज का ये विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्ष्य है कि भाजपा कैसे नारीशक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश में नारीशक्ति वंदन अभियान शुरू किया था, इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया। आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत की नारीशक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारीशक्ति की आर्थिक

उन्होंने कहा कि यहां आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी

कांग्रेस सत्ता में आई तो रद्द कर देंगे सीएए : पवन खेड़ा

मणिपुर नहीं जाने पर की प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना

गुवाहटी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) को रद्द कर देंगे। उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा के दौरान राज्य का दौरा नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की है। गुवाहटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अबतक असम के लिए कट ऑफ तारीख 1971 बहुत खास था, लेकिन सीएए के आने से उनसे ये अधिकार छिन लिए जाएंगे। इसके बाद उनके लिए कट ऑफ तारीख 2014 होगी।



उन्होंने बताया कि असम समझौते के अनुसार, बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले नागरिकों की कट ऑफ तारीख 25 मार्च 1971 है। सीएए के तहत मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों को नागरिकता प्रदान करना चाहती है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं। पवन खेड़ा ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम सीएए रद्द कर देंगे। उन्होंने आगे बताया, 2019 में सीएए को संसद में पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद उत्तर-पूर्वी राज्यों में इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले वह सीएए लागू करने के नियमों को जारी करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे के दौरान कांग्रेस ने मणिपुर नहीं जाने पर उनकी आलोचना की थी। पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से क्यों डर रहे हैं? हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जब वह यहां आए तो कम से कम आधे घंटे के लिए राज्य का दौरा करें। मणिपुर में पिछले साल तीन मई से जारी जातीय हिंसा में अबतक 219 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत

बिस्वा सरमा को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि जनता उन्हें जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस असम में अच्छा प्रदर्शन करेगी।

भाजपा में शामिल हुए छिंदवाड़ा के सात कांग्रेस पार्षद

भोपाल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ को उस समय झटका लगा जब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नगर निगम में उनकी पार्टी के सात पार्षदों ने लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति निष्ठा बदल ली। नगरसेवक अपने समर्थकों के साथ मंगलवार रात राज्य की राजधानी भोपाल में राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आवास पर फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाते हुए भाजपा में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ का गढ़ है, जो वर्तमान में इस विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राज्य से गुजर रही है। भाजपा की विज्रति में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले सात पार्षद रोशनी सल्लम, लीना तिरकम, सतीषी वाडिवार, दीपा मोहरे, जगदीश गोदरे, चंद्रभान ठाकरे और धनराज भावकर हैं।

स्टील प्रमुख समाचार

भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम टेस्ट मैच आज से

धर्मशाला। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 7 मार्च से खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों टीमों भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 9 बजे से धर्मशाला में खेलने उतरेंगी। टीम इंडिया ने पहले ही सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा चुकी है। पांचवें टेस्ट में टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। इससे पहले जसप्रीत बुमराह को रॉन्ची में हुए चौथे टेस्ट में आराम दिया गया था, लेकिन पांचवें मुकाबले में उनकी वापसी हो सकती है। वर्कलोड की वजह से चौथे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था। पांचवें टेस्ट में अब बुमराह वापसी के लिए तैयारी हैं। बुमराह का प्रदर्शन इस सीरीज में अब तक लाजवाब रहा है। तीन मैचों में भारतीय तेज गेंदबाज 17 विकेट अपने नाम कर चुका है। बुमराह की वापसी से टीम इंडिया का पेस अटैक काफी मजबूत होगा। बुमराह की वापसी के लिए आकाश दीप या मोहम्मद सिराज में से किसी एक को जगह बनाने होगी। वहीं मेहमान टीम ने धर्मशाला टेस्ट के लिए टीम में एक बदलाव किया। जहां ओली रॉबिन्सन की जगह तेज गेंदबाज मार्क वुड को शामिल किया गया। वुड आखिरी बार राजकोट में तीसरे टेस्ट में दिखे थे, जहां पहली पारी में चार विकेट लेने के बाद उन्हें दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं मिला था। पहले टेस्ट में वुड एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे।

74 हजार टी आर सेसेक्स निपटी भी नए शिखर पर

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार एक और नया कीर्तिमान रचते हुए बुधवार को अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया और बीएसई सेसेक्स 74 हजार अंक के लेवल को पार कर गया। शेयर बाजार बूँद और चुनिंदा आईटी शेयरों में खरीदारी और यूरोपीय बाजारों में बढ़त के साथ उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में शुरुआती गिरावट से उबरते हुए बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेसेक्स आज गिरावट के साथ 73,587.70 अंक पर खुला और कारोबार के दौरान 73,321.48 अंक के नीचेले स्तर तक गया। अंत में सेसेक्स 0.55 प्रतिशत या 408.86 अंक की बढ़त लेकर 74,085.99 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निपटी-50 भी 0.53 फीसदी या 117.75 अंक की बढ़त लेकर 22,474.05 पर बंद हुआ। निपटी की 35 कंपनियों के शेयर ग्रीन जबकि 15 के रेड निशान में बंद हुए।

भारत 2031 तक होगा 'अपर मिडिल-इनकम' वाला देश

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाते हुए बुधवार को कहा कि यह 2031 तक अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा और अर्थव्यवस्था भी दोगुनी होकर सात लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी 'इंडिया आउटलुक' रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू संरचनात्मक सुधारों और चक्रवृत्ति स्थितियों से समर्थन मिलेगा और यह वर्ष 2031 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपनी वृद्धि संभावनाओं को बरकरार रखने के साथ उत्तम सुधार भी कर सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में उम्मीदी से बेहतर 7.6 प्रतिशत वृद्धि रहने के बाद भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 में थोड़ा मध्यम होकर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

कार्ड जारी करते समय बैंक नेटवर्क चुनने का विकल्प दें

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पात्र ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क में से एक को चुनने का विकल्प सुझाया कराएँ। केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं से यह भी कहा है कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ कोई भी ऐसा समझौता या व्यवस्था न करें जो ग्राहकों को दूसरे नेटवर्क की सेवाएँ लेने से रोकता हो। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक परिपत्र में कहा, समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएँ ग्राहकों के लिए विकल्प उपलब्ध कराने के लिहाज से अनुकूल नहीं हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, ऐसी स्थिति में यह निर्देश दिया जाता है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।

म्युचुअल फंड की इस स्कीम में निवेश कर बचाएँ टैक्स

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो निवेश पर बेहतर रिटर्न के साथ साथ टैक्स में छूट भी चाहते हैं। ऐसे लोग फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बजाय इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि इक्विटी में निवेश कर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी में निवेश पर क्या डिडक्शन (कटौती) का फायदा मिलेगा? उत्तर है हाँ। इक्विटी में भी निवेश कर आप डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। ईएलएसएस, एनपीएस और यूएपीएस ऐसी ही तीन स्कीम हैं। लेकिन ईएलएसएस और यूएपीएस में निवेश पर डिडक्शन का फायदा आपको सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलेगा। जबकि एनपीएस में निवेश पर टैक्स बर्निफिट नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं में मिलता है।

जीडीपी के चमकदार आंकड़ों के बीच उभरती चिंताएं

अनिल तिवारी
जीडीपी में देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में तेजी से बढ़कर 8.4% हो गई है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी तिमाही के लिए 6.5% और एमबीआई रिसर्च में 6.7 से 6.9% तक रहने का अनुमान जताया था। लेकिन एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के ताजा आंकड़ों में अनुमान से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है जिसका श्रेय विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन को दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इंधन सेक्टर की ग्रीन पिछले 15 महीने में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। जनवरी में कोर सेक्टर की वृद्धि दर साल भर पहले के मुकाबले 3.6 प्रतिशत रही

है। कोर सेक्टर में शामिल 8 प्रमुख बुनियादी क्षेत्र में से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी में कमजोरी का असर ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ा है। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक कोर सेक्टर की ग्रोथ 7.7 प्रतिशत रही है। इसी तरह जीडीपी के चमकदार आंकड़ों के बीच खेती और खपत का हाल अब भी बेहाल है। ग्रामीण मांग बहुत कमजोर है, शहरों में भी कोई तेजी नहीं है। जब तक खपत की रफ्तार नहीं बढ़ेगी, निजी निवेश में भी तेजी नहीं आएगी। सुखद है कि खुदरा महंगाई दैनिक उभारण की वस्तुओं के दाम घटने से निचले स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि मूल्य सूचकांक का बढ़ना घटना अगर खाद्य उत्पादों पर ही निर्भर रहता है तो यह संतोषजनक नहीं है। असली मामला औद्योगिक उत्पादन की दर का है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सालाना आधार पर

आसपास पहुंच चुकी है। यद्यपि बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रेस में जीडीपी को आधार बनाया गया है जबकि दूसरा पक्ष यह है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विकसित होने में हमने खुद ही 2047 तक का समय सोचा है। जिस इंग्लैंड को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत उससे बहुत नीचे है। अभी हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग 2100 डॉलर है जबकि आज उच्च आय वाला देश उसे माना जाता है जहां प्रति व्यक्ति आय 12000 डॉलर से अधिक हो। यानी अभी हम उच्च आय वाले देश के छवें हिस्से के बराबर हैं। विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के 197 देशों की सूची में भारत का स्थान 142 वें पायदान पर है। आर्थिक सुधार और विकास की तेज रफ्तार के जरिए भारत का लक्ष्य 2047 तक

अपनी अर्थव्यवस्था को आज से 10 गुना अधिक का बनाना है। आर्थिक जानकारों के मुताबिक इसके लिए हमें 8% से ऊपर की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करनी होगी। चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में यह लक्ष्य देश ने हासिल किया है। अगर जब हम वित्तीय वर्ष की आर्थिकी का लेखा-जोखा करते हैं और इसकी संभावनाओं को टटोलते हैं तो कुछ विलोम स्थितियां न सिर्फ सचेत करती हैं बल्कि नित नए आंकड़े चौंकाते भी हैं। मोटे तौर पर विकसित देश बनने के लिए जरूरी है कि देश के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा हो, उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल रही हो और नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक हो। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 132वीं है जबकि दुनिया के बेहतर शिक्षण संस्थानों के मामले में भारत 149 वें स्थान पर है।

